राजस्थान समसामयिकी मार्च, 2022

Useful For All Competitive Exams

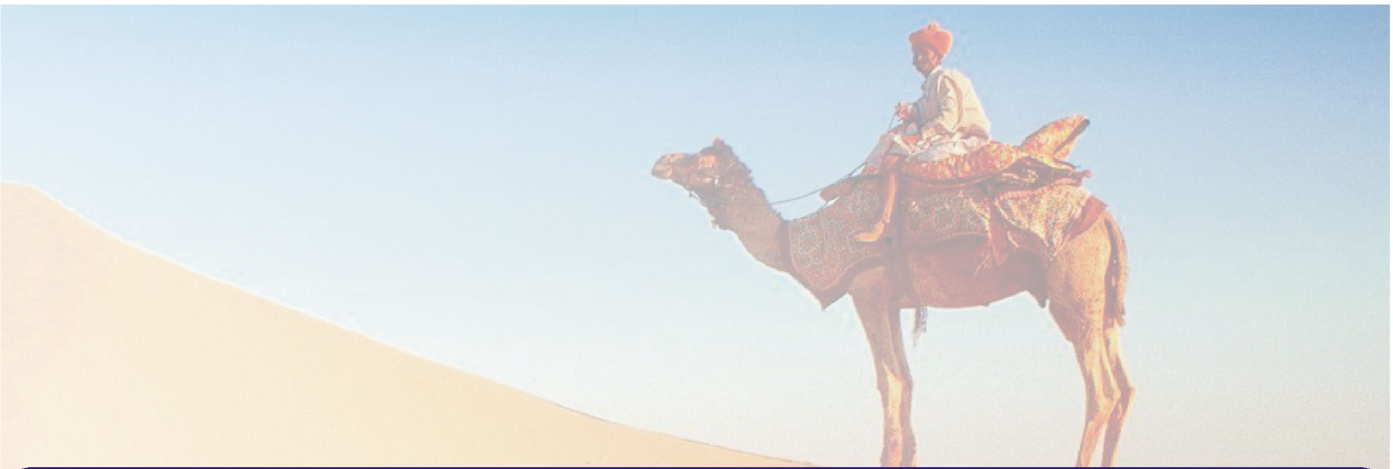

प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सम-सामयिक घटनाओं की मासिक पत्रिका

संजीव प्रकाशन, जयपुर

website : www.sanjivprakashan.com

राजस्थान समसामयिकी मार्च, 2022
(Current News from Daily News Papers)

News Paper of 1 March, 2022

- **राजस्थान में आयोग, बोर्ड और निगमों में 74 राजनीतिक नियुक्तियां दी गई–**
राजस्थान सरकार ने 28 फरवरी, 2022 को आयोग, बोर्ड और निगमों में 7 अध्यक्ष व उपाध्यक्ष और 67 सदस्यों सहित 74 को राजनीतिक नियुक्तियां दी है।

आयोग/बोर्ड/निगम	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष
राजस्थान व्यापार कल्याण बोर्ड	अध्यक्ष–सुरेश मोदी (विधायक)
भवन एवं अन्य सनिर्माण राज्य स्तरीय सलाहकार समिति (श्रम विभाग)	अध्यक्ष–गजराज खटाणा (विधायक)
राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड	अध्यक्ष– अर्चना शर्मा उपाध्यक्ष– मीनाक्षी चन्द्रावत
राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट बोर्ड	उपाध्यक्ष–सुचित्रा आर्य
राजस्थान पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग	उपाध्यक्ष–दर्शनसिंह गुर्जर
राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग	उपाध्यक्ष–अवधेश दिवाकर बैरवा

बोर्ड/निगम/आयोग	सदस्य
राजस्थान राज्य महिला आयोग	अंजना मेघवाल, सुमन यादव, सुमित्रा जैन
राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग	प्रताप यादव
राजस्थान वक्फ विकास परिषद	शब्बीर हुसैन खान, सलीम नागौरी, अब्दुल रज्जाक, जिंदरान, इरफान चौधरी
राजस्थान मदरसा बोर्ड	हसन महमूद कासमी, सलीम सोढ़ा, सईद सउदी, मोहम्मद अतीक, लाल मोहम्मद, मोहम्मद असगर कुरैशी हाजी रहमतुल्ला कासी
बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं समन्वय हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति	राजेश चौधरी, निजाम मोहम्मद
राजस्थाान राज्य समाज कल्याण बोर्ड	रशीदा बानु, रूक्ष्मणी कुमारी, चयनिका उनियाल
राजस्थान जन अभियोग निराकरण समिति	भंवर मेघवंशी, शंकर डंगायच, शब्बीर अहमद
राजस्थान युवा बोर्ड	हेमराज शर्मा, महेश मोरदिया, नितेश पुष्करणा, सुनिल शर्मा, युगल किशोर बबलेश, लोकेश मीणा, रूकमानन्द स्वामी, जितेन्द्र सिंह नरूका
राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	अजीत यादव, अरूण कुमावत, कैलाश सौयल, प्रकाशचन्द्र जाट
राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद	अजाद सिंह राठौड़, हरीश यादव, मनोज पाण्डे, अभिमन्यु पूनियां, आभासिंह गुर्जर, दिनेश गहलोत
राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण	करणसिंह उचियारड़ा, भवानी शंकर माली
व्यापार कल्याण बोर्ड	ज्योति खण्डेलवाल, अशोक जैन संगरीया
राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड	अशोक धारनिया, ओम राजोरिया
राजस्थान स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज डवलपमेन्ट बोर्ड	प्रेम पाटीदार, मनीष धारनिया, लल्लूराम सैनी, प्रदीप काबरा
विप्र कल्याण बोर्ड	राजकुमार किराडू, पवन शर्मा, सीताराम शर्मा 'नेहरू', राजेश रामदेव, पंडित सुरेश शर्मा
बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड	घनश्याम मेहर, गोवर्धन सिंह चौहान, सुशील आसोपा, पुनीत जांगु
राजस्थान वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड	गोविन्द मेहनसरिया, आत्माराम गोयल, शांति प्रसाद हर्ष
पशुधन विकास बोर्ड	कुन्दन यादव, रतन जणवा, जुगल भाटी, गोदाराम देवासी

संजीव प्रकाशन
संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

News Paper of 2 March, 2022

- **राजस्थान में 1800 मेगावाट के दो नए सोलर पार्क को मंजूरी मिली–**

हाल ही में मार्च, 2022 में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राजस्थान में दो नए 1800 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क लगाने की मंजूरी दी ये सोलर पार्क दो चरण में जैसलमेर और बीकानेर में लगाए जाएंगे।

पहले चरण में 800 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क जैसलमेर में राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के माध्यम से तैयार किया जाएगा।

दूसरे चरण में एक हजार मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क बीकानेर में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की सहायक कंपनी राजस्थान सोलर पार्क डवलप करेगी।

राजस्थान में अब तक 10560 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित की जा चुकी है तथा राजस्थान सर्वाधिक सौर ऊर्जा विकसित करने वाला देश का पहला प्रदेश बन चुका है।

विश्व का सबसे बड़ा (2245 मेगावाट क्षमता वाला) सोलर पार्क जोधपुर के भड़ला में है।

News Paper of 4 March, 2022

- **राजस्थान में नए जिलों के गठन के लिए कमेटी बनाई–**

3 मार्च, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई घोषणा के फलस्वरूप राजस्थान में नये जिलों के गठन के लिए राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और राजस्थान के पूर्व निर्वाचन आयुक्त राम लुभाया को बनाया गया है। यह समिति 6 महिने के भीतर अपनी सिफारिश देगी। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही नए जिले बनाए जाएंगे। राजस्थान में 50 नए जिले बनाए जाने की मांग की जा रही है।

News Paper of 5 March, 2022

- **केन्द्र सरकार ने राजस्थान में ₹250 करोड़ के अपशिष्ट उपचार की मंजूरी दी : कचरे से खाद व ऊर्जा बनेगी–**

केन्द्र सरकार ने हाल ही में राजस्थान में ₹250 करोड़ के विरासती अपशिष्ट उपचार की मंजूरी दी है। इससे राजस्थान कचरा मुक्त राज्य बनने की ओर बढ़ रहा है जिससे राज्य को 'लक्ष्य जीरो डंपसाइट' हासिल करने में भी मदद मिलेगी। सम्पूर्ण राज्य के 198 शहरी स्थानीय निकायों से प्रतिदिन लगभग 4800 मीट्रिक टन (एम.टी.) ठोस अपशिष्ट पैदा होता है। कचरे से खाद और ऊर्जा बनाई जाएगी।

News Paper of 6 March, 2022

- **राजस्थान हाइकोर्ट के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश अकील कुरेशी सेवानिवृत्त हुए–**

राजस्थान उच्च न्यायालय के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश 6 मार्च, 2022 को सेवानिवृत्त हुए वे 12 अक्टूबर 2021 से 6 मार्च, 2022 तक इस पद पर रहे। वर्तमान में 6 मार्च, 2022 को ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव को राज. उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। मनीन्द्र मोहन राजस्थान हाइकोर्ट में 18 अक्टूबर, 2021 से जज के रूप में कार्यरत है।

- **स्मार्ट सिटी मिशन में राजस्थान को पूरे देश में दूसरा स्थान मिला–**

भारत में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 बड़े शहर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। इस वर्ष स्मार्ट सिटी के वार्षिक कार्य आकलन के आधार पर राजस्थान को दूसरा स्थान मिला है। राजस्थान में 2021–22 में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत ₹1222 करोड़ खर्च किए गए। राजस्थान में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 4 शहर–जयपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा को शामिल किया गया है वर्ष 2021–22 में इन शहरों की रैंकिंग निम्न रहीं–

शहर	स्कोर	रैंक 2021-22	रैंक 2020-21
जयपुर	77.86	10	36
उदयपुर	83.69	9	8
कोटा	53.11	14	11
अजमेर	46.71	22	29

News Paper of 9 March, 2022

- **बीकानेर की छात्रा गुंजन तोदी को महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय में एक दिन का मानद कुलपति बनाया–**

8 मार्च, 2022 को महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा छात्रा गुंजन तोदी को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक दिन का मानद कुलपति बनाया गया। कुलपति पद ग्रहण करने के लिए छात्रा गुंजन तोदी ने राज्यपाल कलराज मिश्र से अनुमति ली।

News Paper of 10 March, 2022

- **मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन्दिरा शक्ति एप लॉन्च किया : महिलाओं की सुरक्षा के लिए उपयोगी होगा–**

9 मार्च, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन्दिरा शक्ति एप का लॉन्च किया। यह एप महिलाओं के प्रति छेड़खानी,

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

दुष्कर्म और यौन प्रताड़ना जैसी शिकायतों पर सुरक्षा मुहैया करवाएगा।

- **राजस्थान प्रदेश में लोक कलाकारों के दैनिक मानदेय में बढ़ोतरी हुई–**

राजस्थान प्रदेश के लोक कलाकारों के दैनिक मानदेय में हाल ही में पर्यटन विभाग की ओर से वृद्धि की गई है। इस वृद्धि के तहत विभिन्न मेले और त्योहारों पर होने वाले कार्यक्रम में इनका दैनिक मानदेय बढ़ाया गया है।

राज्य व राज्य से बाहर के लिए नई दरें

- **ग्रुप लीडर**–2500 रुपए
- **दैनिक भत्ता**–300 रुपए व कन्वेंस 75 रुपए
- **अन्य कलाकार**–750 रुपए और 250 रुपए दैनिक भत्ता और कन्वेंस 75 रुपए

मुख्य प्रस्तुति के अतिरिक्त पूर्वाभ्यास दिवस

- **ग्रुप लीडर**–1000 रुपए
- **दैनिक भत्ता**–300 रुपए व कन्वेंस 75 रुपए
- **अन्य कलाकार**–500 रुपए और दैनिक भत्ता 250 रुपए और कन्वेंस 75 रुपए

विदेश में कार्यक्रम होने पर आइसीसीआर से सूचीबद्ध नहीं होने पर

- **ग्रुप लीडर**–2500 रुपए दैनिक भत्ता 1250 रुपए और कन्वेंस 750 रुपए

विदेश में कार्यक्रम होने पर आइसीसीआर से सूचीबद्ध होने पर

- **ग्रुप लीडर**–35000 दैनिक भत्ता 1250 और कन्वेंस 750 रुपए
- **अन्य कलाकार**–7000 दैनिक भत्ता 750 और कन्वेंस 750 रुपए।

News Paper of 21 March, 2022

- **ग्रीन एनर्जी के लिए राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा को पहला हाइड्रोजन हब बनाया जाएगा–**

राजस्थान सरकार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने जा रही है। यहां न्यूक्लियर प्लांट में स्वच्छ न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग कर पिंक हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र लगाया जाएगा, जो कि देश में ग्रीन हाऊस गैस के इमिशन कम करने में मददगार होगा। यह संयंत्र न्यूक्लियर क्षेत्र का पहला पायलट प्रोजेक्ट होगा।

- **राजस्थान के कोटा जिले के सुल्तानपुर में मॉडल रूरल हैल्थ रिसर्च यूनिट बनेगी–**

केन्द्र सरकार के आईसीएमआर प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के कोटा जिले के सुल्तानपुर में मॉडल रूरल हैल्थ रिसर्च यूनिट बनेगी। यह यूनिट ग्रामीण आबादी में फैलने वाली बीमारियों और उनकी जरूरतों समेत विभिन्न बिन्दुओं पर रिसर्च करेगी। यह यूनिट कोटा मेडिकल कॉलेज कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के अधीन संचालित होगी।

यह यूनिट इस तरह की राजस्थान की दूसरी यूनिट होगी। इससे पहले एक यूनिट जयपुर ग्रामीण में एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज के नियंत्रणाधीन संचालित है।

- **राजस्थान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनवरी, 2022 तक ₹57,803 करोड़ का निर्यात किया–**

राजस्थान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के शुरुआती 10 महिनों अर्थात् जनवरी, 2022 तक ₹57,803 करोड़ का निर्यात किया जो कि पिछले वर्ष के समान अवधि से लगभग ₹5 हजार करोड़ ज्यादा है। इसमें फरवरी-मार्च के निर्यात को जोड़ने के बाद लगभग यह गत वर्ष से ₹10,000 करोड़ से अधिक हो सकता है।

राजस्थान ने निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए मिशन निर्यातक बनो कार्यक्रम के तहत 6 हजार से अधिक नए आईईसी लाइसेंस जारी किए तथा नई निर्यात प्रोत्साहन नीति भी बनाई।

राजस्थान से सर्वाधिक निर्यात निम्न देशों में किया गया–

अमेरिका	₹14707 करोड़
यू.के.	₹3464.38 करोड़
जर्मनी	₹2809.06 करोड़
यू.ए.ई.	₹2706.27 करोड़
बांग्लादेश	₹2232.97 करोड़

राजस्थान से सर्वाधिक विदेशी निर्यात करने वाले जिले–

जिला	₹ करोड़ में
बीकानेर	607.60
जोधपुर	7395.44
चित्तौड़गढ़	4187.92
उदयपुर	3038.58
बांसवाड़ा	760.04
अलवर	12169.30
जयपुर	17717.49
अजमेर	1437.71
भीलवाड़ा	4421.96
कोटा	1734.68

News Paper of 22 March, 2022

- **राजस्थान विधानसभा में वर्ष 2022-23 का राजस्थान सरकार का बजट पास हुआ : नवीन घोषणाएं भी की गई–**

21 मार्च, 2022 को राजस्थान विधानसभा में वर्ष 2022-23 का

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

राजस्थान सरकार का बजट पास हुआ। पारित बजट में नवीन घोषणाएं भी की गई जो निम्न हैं–

- एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी व ईबीसी के साथ अब अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को भी अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना का लाभ मिलेगा।
- महिलाओं को कर्ज देने के लिए जयपुर में अलग से महिला को-ऑपरेटिव बैंक खोला जाएगा। सरकार बैंक को शुरुआत में ₹250 करोड़ का फंड देंगी।
- ग्रामीण ओलम्पिक्स में जिला एवं राज्य स्तर के विजेताओं को पंचायत कोन्ट्रेक्चुअल (संविदा) काडर के रिक्त पदों की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी।
- राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन होगा।
- विशेष योग्यजन को पेंशन के साथ एक हजार रुपए मासिक मदद मिलेगी।
- प्रशासन गांवों के संग और शहरों के संग अभियान का समय 31 मार्च, 2023 तक बढ़ाया गया।
- यूक्रेन-रशिया युद्ध की स्थितियों से सबक लेकर प्रदेश के मेडिकल छात्रों को यहीं बेहतर सुविधाएं देने व निजी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोलने, वर्तमान मेडिकल कॉलेजों के विस्तार के लिए नई नीति बनेगी।
- 2 लाख बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- शिक्षा का अधिकार के तहत निजी स्कूलों में 12वीं कक्षा की छात्राओं का इंद्रा महिला शक्ति निधि से फीस का पुनर्भरण होगा।
- ओलम्पिक, एशियन एवं राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों, अर्जुन व द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ियों, पैरा खिलाड़ियों और कोच को 40 वर्ष की उम्र पूरी करने पर 20 हजार रुपए प्रतिमाह की पेंशन दी जाएगी।
- राज्य कार्मिकों की वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी तथा यह निश्चित समय पर टिप्पणी नहीं करने पर ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगी तथा डीपीसी भी वर्ष में दो बार होगी।
- 500 राजकीय प्रा. विद्यालयों को उ.प्रा. विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा एवं 500 राजकीय विद्यालयों में नए विषय व संकाय खोले जाएंगे।
- 100 नए जनता क्लिनिक खोले जाएंगे तथा 50% राशि विधायक के देने पर उसकी सिफारिश से जगह को प्राथमिकता दी जाएगी।
- भूमि कब्जा, बैंक, जमापूंजी धोखाधड़ी, बीमा, मनी लाउंड्रिंग, झूठे दिवालियापन तथा फर्जी कम्पनियों के गठन कर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ वित्त विभाग के अधीन डाइरेक्ट्रेट ऑफ इकॉनोमिक ऑफिस बनेगा।
- ठेका पर लगे कर्मचारियों को संविदाकर्मियों की तरह नियमित भर्तियों में 10, 20, 30 बोनस अंक का लाभ मिलेगा।
- कोविड की परिस्थिति को देखते हुए मेडिकल हेल्थ वोलेंटियर फोर्स का गठन होगा।
- डिजिटल लर्निंग के लिए ई-लाइब्रेरी बनेगी इससे 9वीं से 12वीं तक की कक्षा के छात्र/छात्राओं को लाभ होगा।
- बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लाई जाएगी, इसमें सम्पूर्ण खर्च का सरकार द्वारा भुगतान (रिएम्बर्स) किया जाएगा।
- माउंट आबू में एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड माउंटेनियरिंग सेंटर खुलेगा।
- सम्भाग मुख्यालयों पर स्टेट ऑफ आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर खुलेंगे। हर जिले के स्टेडियम में ओपन जिम होगी।
- गाड़िया लोहारों का आवास अनुदान ₹70 हजार से बढ़ाकर एक लाख बीस हजार रुपये होगा।
- यात्री वाहन, बस व टैक्सी एम्बुलेंस में व्हीकल ट्रेकिंग डिवाइस व पेनिक बटन लेंगेंगे और कमांड कट्रोल सेंटर स्थापित होगा।
- आबादी क्षेत्र में स्थित 25 जेलों को खुली जगह पर स्थानान्तरित करने के लिए डीपीआर बनेगी।
- ऐसे परिवार जिसमें दिव्यांग, विधवा व बुजुर्ग सदस्य ही हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना। इनको सेवा प्रेरक घर बैठे सरकारी योजनाओं से जोड़ेंगे।
- शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाने के लिए फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल कमीशन की स्थापना होगी।
- विमुक्त, घुमंतु, अर्द्धघुमंतु वर्ग के उत्थान के लिए डीनोटिफाइड ट्राइब्स पॉलिसी बनेगी।

News Paper of 23 March, 2022

- **स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की फरवरी माह की परफोरमैंस रैंकिंग में राजस्थान पहले स्थान पर आया–**

भारतीय स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की फरवरी, 2022 माह की मासिक परफोरमेंस रैंकिंग के तहत राजस्थान पहले स्थान पर रहा है। यह रैंकिंग 100 शहरों में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा के तहत मिली है।

स्मार्ट सिटी रैंकिंग के तहत पहले स्थान पर रहे राजस्थान को 90.40 अंक, दूसरे स्थान पर रहे झारखण्ड को 88.73 अंक तथा तीसरे स्थान पर रहे उत्तर प्रदेश को 71.66 अंक मिले हैं।

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

राजस्थान के स्मार्ट शहरों की स्थिति–

स्मार्ट सिटी	स्कोर	रैंकिंग
उदयपुर	104.45	6
कोटा	95.03	8
अजमेर	88.18	14
जयपुर	75.70	21

देश के 100 स्मार्ट सिटी में प्रथम तीन स्थानों पर क्रमशः भोपाल, इंदौर और वाराणसी रहे हैं।

News Paper of 24 March, 2022

- **राजस्थान विधानसभा में राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि विधेयक पारित–**
23 मार्च, 2022 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि विधेयक पारित हुआ। इसके तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रत्येक के विकास के लिए अलग से कोष बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक के लिए ₹500 करोड़ दिए जाऐंगे।
- **राजस्थान विधानसभा में राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित–**
23 मार्च, 2022 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित हुआ। इसके तहत अब राज्य के शहरी निकायों की भर्ती परीक्षा फिर से राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) करायेगा।

News Paper of 25 March, 2022

- **राजस्थान विधानसभा में नकल रोकने के लिए सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) विधेयक-2022 पारित–**
24 मार्च, 2022 को राजस्थान विधानसभा में अनुचित साधनों का प्रयोग व पेपरलीक की घटनाओं को रोकने के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) विधेयक-2022 पारित किया गया। इसमें राज्य में होने वाली सभी तरह की भर्ती प्रतियोगी परीक्षाएं शामिल होंगी। जबकि यह विधेयक बोर्ड/विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए लागू नहीं होगा।
इस कानून के तहत नकल माफिया या गिरोह द्वारा अपराध से प्राप्त की गई सम्पत्ति को जब्त किया जा सकेगा।

इस विधेयक के तहत सजा का निम्न प्रावधान रहेगा–

- मिलीभगत कर अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले परीक्षार्थी सहित अन्य व्यक्तियों को 5 से 10 वर्ष तक की सजा तथा 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान होगा।
- अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले परीक्षार्थियों को तीन साल तक का कारावास। न्यूनतम एक लाख रुपए का अर्थदंड। परीक्षा से दो वर्ष के लिए बाहर किया जाएगा।
- अपराध से प्राप्त की गई सम्पत्ति की जब्ती। कुर्की और राजसात करने के संबंध में प्रावधान। अनुसंधान अधिकारी राज्य सरकार की पूर्वानुमति से चल या अचल सम्पत्ति को जब्त कर सकेगा।
- मैनेजमेंट या संस्था के अपराध करने पर संस्था को हमेशा के लिए बैन किया जा सकेगा।
- दोषी पाए जाने पर परीक्षा पर हुए खर्चे की भरपाई के लिए संस्था या प्रबंधन की सम्पत्ति को नीलाम किया जाएगा।
- अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और नॉन कम्पाउंडेबल होंगे। अपराधों की ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट का प्रावधान किया। अनुसंधान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी या उससे ऊपर के अधिकारी ही करेंगे।

News Paper of 26 March, 2022

- **राष्ट्रीय हैण्डबॉल प्रतियोगिता में मेजबान टीम राजस्थान को रजत पदक मिला–**
25 मार्च, 2022 को 50वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता के मुकाबले में मेजबान राजस्थान टीम को रजत पदक मिला। इसमें सर्विसेज विजेता रहा।

News Paper of 27 March, 2022

- **जयपुर में दक्षिणी पश्चिमी कमान का अलंकरण समारोह हुआ–**
26 मार्च, 2022 को जयपुर में दक्षिण-पश्चिम कमान का अलंकरण समारोह हुआ। इस समारोह में लेफ्टिनेंट जनरल ए एस भिंडर ने समारोह में कुल 14 गैलंट्री सेना मेडल, 1 युद्ध सेवा मेडल, 4 डिस्टिंगग्विश्ट सेना मेडल और 5 विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किए गए। कुल 24 पुरस्कार दिए गए जिसमें 15 सैन्य अफसरों, 3 जूनियर कमीशंड अफसरों और 6 सैनिक शामिल किए गए।
- **राजस्थान सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार से कोयला खनन की अनुमति मिली–**
हाल ही में मार्च, 2022 में राजस्थान सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार से परसा ईस्ट-कांटा बासन कोल ब्लॉक के द्वितीय चरण के तहत 1136 हेक्टेयर जमीन से कोयला खनन की अनुमति मिली है। राजस्थान को यहां से 15 मीट्रिक टन कोयला प्रतिवर्ष मिलेगा।

News Paper of 28 March, 2022

- **राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को SGST में छूट अब 31 मार्च, 2023 तक मिलेगी–**

संजीव प्रकाशन

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

हाल ही में राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को SGST की छूट अवधि को एक वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 तक कर दिया गया है, पहले यह छूट केवल 31 मार्च, 2022 तक निर्धारित थी। इन वाहनों पर 2.5 प्रतिशत SGST है, जिसे मुक्त (Free) किया गया है।

News Paper of 31 March, 2022

- **राजस्थान में विद्युत तंत्र को मजबूत करने के लिए ₹18,358 करोड़ की प्लानिंग को मंजूरी दी गईः स्मार्ट मीटर एवं वितरण ढांचे का सुदृढ़ीकरण होगा –**

मार्च, 2022 में ऊर्जा मंत्रालय ने राजस्थान में विद्युत वितरण तंत्र के सुदृढ़ीकरण, विद्युत लॉस कम करने, स्मार्ट मीटरिंग, औसत राजस्व वसूली अंतर को खत्म करने की ₹18,358 करोड़ की प्लानिंग को मंजूरी दी है।

इसमें कार्य केन्द्र सरकार की रिफॉर्म बेस्ड एवं रिजल्ट लिंक्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत होगा। इसमें कार्य दो चरण में होगा। प्रथम चरण में स्मार्ट मीटरिंग के लिए ₹9678 करोड़ और विद्युत वितरण तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए ₹8680 करोड़ स्वीकृत किए है।

प्री-पेड स्मार्ट मीटरिंग एवं सिस्टम मीटरिंग के अन्तर्गत कार्य–

- सभी फीडरों को कम्यूनिकेबल एमआइ, एमआर मीटरों के साथ इस वर्ष दिसंबर तक मीटर्ड करना।
- राजस्थान में चिह्नित सभी 29 अमृत सिटी विद्युत खंड (जहां विद्युत लॉस 15 प्रतिशत से अधिक है) के औद्योगिक व व्यावसायिक श्रेणी के सभी उपभोक्ता, ब्लॉक स्तर व इससे ऊपर सभी सरकारी, स्वायत्तशासी, बोर्ड में दिसम्बर, 2023 तक प्री-पेड मीटर लगाना।
- चिह्नित सभी वितरण ट्रांसफॉर्मर पर संचार प्रणाली युक्त मीटरिंग दिसंबर-2023 तक करना।

वितरण ढांचे का सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत कार्य–

- 33 केवी एवं 11 केवी अधिक भार वाले फीडरों का विघटन।
- नए 33 केवी सब स्टेशनों का निर्माण।
- पुराने कंडक्टर को बदल कर नए अधिक क्षमता के कंडक्टर लगाना।
- विद्युत चोरी क्षेत्रों में कंडक्टर को एरियल बंच्ड केबल से बदलना।
- इलेक्ट्रीकल वाहन चार्जिंग सब स्टेशन के लिए ढांचा तैयार करना।
- हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ढांचे का दायरा बढ़ाना।

- **हाड़ौती क्षेत्र की परवन सिंचाई परियोजना को केन्द्र सरकार से ₹733.86 करोड़ की मंजूरी मिली–**

राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र की महत्वाकांक्षी परवन सिंचाई परियोजना को केन्द्र सरकार की सहमति मिली है। इसके तहत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से ₹733.86 करोड़ की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह परियोजना राजस्थान के झालावाड़, कोटा और बारां जिलों के लिए लाभदायी होगी।

- **राजस्थान का 73वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया–**

30 मार्च, 2022 को राजस्थान का 73वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसके तहत सम्पूर्ण राज्य में इसे 'राजस्थान दिवस' के रूप में मनाकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

राजस्थान का निर्माण सात चरणों में पूर्ण हुआ था जो कि निम्न है–

चरण	नाम	शामिल रियासतें	दिनांक
1.	मत्स्य संघ	अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली	17-03-1948
2.	राजस्थान संघ	बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा व टोंक	25-03-1948
3.	राजस्थान संयुक्त संघ	उदयपुर का राजस्थान संघ में विलय	18-04-1948
4.	वृहद राजस्थान	राजस्थान संयुक्त संघ में बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर व जोधपुर का विलय	30-03-1949
5.	वृहद संयुक्त राजस्थान	वृहद राजस्थान व मत्स्य संघ का विलय	15-05-1949
6.	संयुक्त राजस्थान	आबू व देलवाड़ा को छोड़ सिरोही रियासत का राजस्थान की 18 रियासतों में विलय	26-01-1950
7.	पुनर्गठित राजस्थान	प्रदेश के गठन की प्रक्रिया पूरी	01-11-1956

❑❑❑

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

संजीव®

47 वर्षों से विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संजीव प्रकाशन द्वारा प्रकाशित प्रतियोगिता परीक्षाओं की पुस्तकें बाजार में उपलब्ध

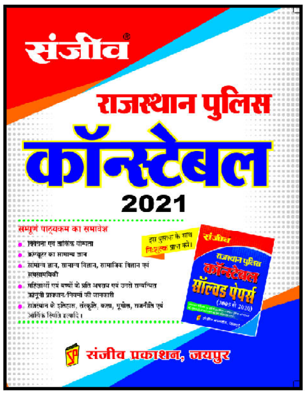

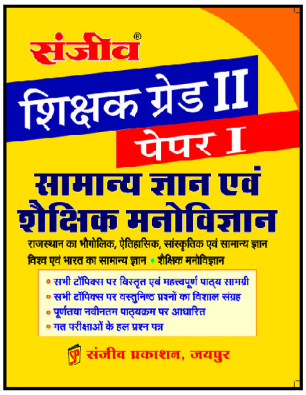

पुस्तकों की विशेषताएँ

✪ नवीनतम पाठ्यक्रम का सम्पूर्ण समावेश ✪ सभी टॉपिक्स पर विस्तृत एवं सटीक विषय सामग्री ✪ परीक्षा में संभावित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का विशाल संग्रह ✪ विगत परीक्षाओं के हल प्रश्न पत्र ✪ राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल व D.EL.ED. (BSTC) गाइड के साथ विगत परीक्षाओं के हल प्रश्न पत्रों की पुस्तिका निःशुल्क ✪ अनुभवी विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार ✪ ग्राम विकास अधिकारी का प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम समान है।

अपने निकटतम पुस्तक विक्रेता से आज ही खरीदें।

संजीव वेबसाइट से निःशुल्क डाउनलोड करें

राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021-22 का सार संग्रह; राजस्थान के बजट 2022-23 का सार संग्रह; राजस्थान, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय समसामयिकी (जनवरी 2021 से प्रत्येक माह)

प्रकाशक-संजीव प्रकाशन, जयपुर

Visit us at : www.sanjivprakashan.com